



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 22, 2002/वैशाख 2, 1924

No. 86]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 22, 2002/VAISAKHA 2, 1924

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2002

सं. टीएएमपी/22/2002-जेएनपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धाराओं 48, 49 और 50 का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार अधिसूचित दरों के मान में अनुपलब्ध दरों वाली सेवाओं के लिए तदर्थ प्रशुल्क वसूल करने की अनुमति देने और इस संबंध में सभी महापत्तन न्यासों और निजी टर्मिनलों के लिए संयुक्त रूप से व्यवस्था शुरू करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता है।

अनुसूची

मामला सं. टीएएमपी/22/2002-जेएनपीटी

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास

आवेदक

आवेश

(अप्रैल, 2002 के 8वें दिन पारित)

यह मामला विशेष कार्गो के प्रहस्तन अथवा अधिसूचित दरों के मान में अनुपलब्ध दरों वाली विशेष सेवाएँ प्रदान करने के लिए पत्तन न्यासों को ऐसी दरों के निर्धारण के अपने प्रस्ताव की इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन की संभावना के मद्देनजर तदर्थ दरें वसूल करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. जेएनपीटी ने अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित बातें कही हैं :-

(i) कई बार निर्यातक/आयातक और पत्तन प्रयोक्ता पत्तन न्यास से विशेष कार्गो के प्रहस्तन के लिए उन

विशेष सेवाओं को प्रदान करने की माँग करते हैं, जिनकी दरें अधिसूचित दरों के मान में उपलब्ध नहीं होती।

- (ii) ऐसी परिस्थितियों में, यह संभव है कि पत्तन महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखकर दर निर्धारित कर सकता है। यदि, यह दर ग्राहक को स्वीकार्य भी हो तो भी पत्तन महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना इस दर को तत्काल प्रचालित नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थितियों में, पत्तन विशेष सेवाओं की अनुमति देने के लिए प्राप्त आवेदनों की व्यवहार्यता की जाँच करने के पश्चात् उपयुक्त दर का प्रस्ताव करता है और उसे महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के पास विचार के लिए भेजता है।
- (iii) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा इस समय अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसार जाँच, मूल्यांकन, अंतिम निर्णय और राजपत्र में अधिसूचना में औसतन कम से कम तीन से छह माह का समय लगता है।
- (iv) यह प्रस्ताव किया गया है कि तेजी से वाणिज्यिक निर्णय लेने को सहज बनाने के लिए ऐसे प्रस्ताव, जो ग्राहक को स्वीकार्य हों, पत्तन को तत्काल प्रभाव से वसूल करने और उन दरों को तीन माह की अवधि तक महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण को प्रस्तावित करने के लिए पत्तन को अनुमति प्रदान की जाए।
- (v) यदि महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण का निर्णय तीन माह के पश्चात् भी नहीं भेजा जाता है तो पत्तन द्वारा दी जाने वाली विशेष सेवाएँ प्रस्तावित दर पर, तब तक जारी रहेंगी, जब तक पत्तन के प्रस्ताव पर महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा निर्णय नहीं ले लिया जाता।
- (vi) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरें बादी प्रभाव से प्रचालित की जा सकती हैं।
- (vii) उपर्युक्त व्यवस्था तेजी से वाणिज्यिक निर्णय लेने में पत्तन को अपेक्षित लचीलापन प्रदान करेगी।

3. जेएनपीटी के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है :-

- (i) उल्लेखनीय है कि महापत्तन न्यासाँ/निजी टर्मिनलों द्वारा वसूल किए जाने वाले प्रशुल्क विधि के अनुसार इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होने चाहिए। प्रचालक अस्थायी अथवा तदर्थ प्रशुल्क (बी) प्रचालित करने के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं ले सकते।
- (ii) अनुभव से पता चला है कि इस प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावों की जाँच और प्रशुल्कों के अनुमोदन में सामान्यतः कम से कम 3-6 माह का समय लगता है।
- (iii) इस पृष्ठभूमि में, जेएनपीटी का प्रस्ताव इस प्रणाली में कुछ लचीलापन लाने के लिए पहल करता है। संभवतः इस प्रस्ताव का आशय उस स्थिति से बचना है, जिसमें पत्तन न्यास ऐसी सेवा पर आने वाली लागत को भुगत करने के लिए उपयुक्त (वर्तमान) प्रशुल्क के अभाव में प्रयोक्ताओं द्वारा अपेक्षित तत्काल (मई) सेवा प्रदान करने से इंकार न करे।

- (iv) निष्पक्ष नियामक तीसरा पक्ष होने के कारण इस प्राधिकरण को किसी भी प्रशुल्क मामले पर निर्णय लेने से पूर्व अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है। बहुत कम स्टॉफ के कारण प्राधिकरण को हो रही कठिनाइयों के बावजूद मामलों को शीघ्रता से निपटाने पर ध्यान दिया जाता है। हमारा अनुभव दर्शाता है कि अधिकांश मामलों में विलंब पतन न्यासों से टिप्पणियों/स्पष्टीकरणों/अतिरिक्त सूचना की प्राप्ति में विलंब के कारण होता है। दस्तावेज/सूचना प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमाएँ विनिर्दिष्ट करने की सांविधिक शक्ति न होने के कारण इस प्राधिकरण के पास ऐसी स्थितियों में मामलों को बन्द करने का रास्ता ही रह जाता है। यह भी स्वीकार करना होगा कि उनके द्वारा दायर अभ्यावेदनों संबंधी मामलों में ऐसा असाधारण निर्णय पतन न्यासों और अधिक महत्वपूर्ण रूप से प्रयोक्ताओं का कोई प्रयोजन पूरा नहीं करेगा।
- (v) यद्यपि, यह प्राधिकरण जेएनपीटी के प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए प्रवृत्त है, परंतु यह जोखना आवश्यक होगा कि तदर्थ दर अंतरिम अवधि में प्रचालित की जानी चाहिए और तुलनात्मक सेवाओं/कार्गों के वर्तमान अधिसूचित प्रशुल्कों पर आधारित होनी चाहिए और इस पर पतन न्यास और संबद्ध प्रयोक्ता के बीच परस्पर सहमति होनी चाहिए।
- (vi) इस प्राधिकरण को पूर्ण औचित्य सहित औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के साथ-साथ तदर्थ दर समानान्तर रूप से लागू की जा सकती है। इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अंतिम दर (दरें) सामान्यतः भावी प्रभाव से लागू होंगी। तदर्थ रूप में अपनाई गई अंतरिम दर को ऐसी मान्यता दी जाएगी, बशर्तें यह पूर्व-प्रभाव से कुछ संयम की अपेक्षा करते हुए अधिक पाई जाएगी।
- (vii) पर्याप्त साक्ष्यानी द्वारा, यह उल्लेखनीय है कि तदर्थ दरें वसूल करने का प्राधिकार केवल उन मामलों में दिया गया है, जहाँ ऐसी दरें अलग-अलग हैं। यह संयुक्त प्रयोक्ता सुविधाओं अथवा वर्तमान प्रशुल्कों में संशोधन के लिए नहीं हो सकती।
- (viii) यह संभव है कि तदर्थ दरों को लागू करने से अंतिम प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए इस प्राधिकरण को अपेक्षित ब्योरे देने में महापतनों/निजी टर्मिनलों की ओर से कुछ ढिलाई बरती जा सकती है। ऐसे मामलों में यदि इस प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित ब्योरे विनिर्दिष्ट समय-सीमा में नहीं दिए जाते हैं तो यह प्राधिकरण तदर्थ दरें वसूल करने के लिए दिए गए सामान्य प्राधिकार को वापस लेने और की गई वसूलियों को वापस करने का आदेश देने के लिए बाध्य होगा।
- (ix) महापतनों में प्रशुल्क निर्धारण के मामले में एकसमान सिद्धांतों, दृष्टिकोणों और मानकों को अपनाने के लिए यह इस प्राधिकरण की उल्लिखित नीति रही है। इसलिए, अन्य महापतन न्यासों और इनमें निजी टर्मिनलों के लिए जेएनपीटी के प्रस्ताव के संदर्भ में दिए गए आदेश के अनुसार व्यवस्था निर्धारित करना उपयुक्त है।

4. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त पैरा 3 में दिए गए तर्कों के अनुसार यह प्राधिकरण सभी महापतन न्यासों और इनमें निजी टर्मिनलों के लिए संयुक्त रूप से निम्नलिखित व्यवस्था का अनुमोदन करता है :-

- (i) जहाँ कहीं भी सेवा/कार्गों के लिए विशेष प्रशुल्क अधिसूचित दरों के मान में उपलब्ध नहीं हैं वहाँ महापतन न्यास/निजी टर्मिनल इस प्राधिकरण को उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

- (ii) प्रस्ताव प्रस्तुत करने के साथ-साथ, तदर्थ आधार पर प्रस्तावित दर तब तक वसूल की जा सकती है, जब तक इस प्राधिकरण द्वारा दर को अंतिम रूप से अधिसूचित नहीं किया जाता।
- (iii) अंतरित अवधि में प्रचलित की जाने वाली तदर्थ दर तुलनात्मक सेवाओं/कार्गो के वर्तमान अधिसूचित प्रशुल्कों के आधार पर होनी चाहिए और पत्तन/टर्मिनल और संबद्ध प्रयोक्ता के बीच परस्पर सहमति होनी चाहिए।
- (iv) इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अंतिम दरें सामान्यतः केवल भावी प्रभाव से लागू होंगी। तदर्थ रूप में अपनाई गई अंतरिम दर इस रूप में स्वीकार्य होगी, बशर्ते यह पूर्व-प्रभाव से कुछ संयम की अपेक्षा करते हुए अधिक पाई जाएगी।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2002

No. TAMP/22/2002-JNPT.—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the proposal of the Jawaharlal Nehru Port Trust for allowing levy of *ad hoc* tariffs for the services for which rates are not available in the notified Scale of Rates and introduces an arrangement in this regard commonly for all the major port trusts and private terminals therein as in the Order appended hereto.

SCHEDULE

No.TAMP/22/2002-JNPT

The Jawaharlal Nehru Port Trust

- - -

Applicant

ORDER

(Passed on this 8th day of April 2002)

This case relates to a proposal from the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) for allowing the Port Trusts to levy *ad hoc* rates for handling of certain cargo or providing specific services for which rates are not available in the notified Scale of Rates, in anticipation of approval by this Authority of its proposal for fixation of such rates.

2. In its proposal, the JNPT has made the following points:
 - (i). Sometimes exporters / importers and port users approach the Port Trust for handling of certain cargo or providing special services for which rates are not available in the notified Scale of Rates.
 - (ii). In such circumstances, it is possible that the port can work out the rate taking into consideration the TAMP guidelines. Even if such a rate is acceptable to the client, the port cannot immediately start operating the rate for want of the TAMP's approval. Under such circumstances, the port proposes a reasonable rate for permitting specific services after examining the viability of the requests received and sends the same to the TAMP for consideration.
 - (iii). As per the procedure currently adopted by the TAMP, the process of scrutiny, evaluation, final decision and Gazette Notification takes on an average at least three to six months.
 - (iv). It is proposed that in such kind of proposals which are acceptable to a client, in order to facilitate taking speedy commercial decisions, the port may be allowed to charge with immediate effect the rates it has proposed to TAMP upto a period of three months.
 - (v). In case the decision of the TAMP is not communicated even after three months, the specific services will continue to be performed by the Port at the proposed rates till a decision is taken by the TAMP on the proposal of the Port.
 - (vi). The rates approved by the TAMP can operate prospectively.
 - (vii). The above arrangement will provide the required flexibility to the Port in taking faster commercial decisions.
3. With reference to the proposal of the JNPT, the following position emerges:-
 - (i). It is noteworthy that the law requires the tariffs levied by the major port trusts / private terminals to be approved by this Authority. The operators do not enjoy any freedom to introduce (even) provisional or *ad hoc* tariffs.
 - (ii). Experience has shown that scrutiny of proposals and approval of tariffs by this Authority usually takes at least 3 - 6 months.
 - (iii). In this backdrop, the JNPT proposal marks an initiative to introduce some flexibility in the system. The idea behind this proposal is, possibly, to avoid a situation of a port trust having to refuse to provide an immediate (new) service required by users for want of a suitable (existing) tariff covering the cost of providing such a service.
 - (iv). This Authority being a third party neutral regulator has to follow the quasi-judicial process before deciding any of the tariff cases. Notwithstanding the severe staff constraints faced by it, care has been taken to dispose of cases expeditiously. Our

1329 6/102-2

experience shows that in most of the cases where delays have occurred they have been due to delays in receipt of comments / clarifications / additional information from port trusts. In the absence of a statutory power to stipulate time limits for submission of documents / information, the only course left to this Authority in such situations is to close the cases. It has to be recognised that such an extraordinary decision will not serve any purpose for the port trusts, and more importantly, for the users in matters relating to representations filed by them.

- (v). While this Authority is inclined to approve the proposal of the JNPT, it will be necessary to add that the *ad hoc* rate to be operated in the interim period must be derived based on the existing notified tariffs for comparable services / cargo; and, it must be mutually agreed upon by the port trust and the concerned user.
- (vi). The *ad hoc* rate can be simultaneously introduced along with submission of a formal proposal with complete justification to this Authority. The final rate(s) fixed by this Authority will ordinarily be effective prospectively. The interim rate adopted in an *ad hoc* manner will be recognised as such unless it is found to be excessive requiring some moderation retrospectively.
- (vii). By way of abundant caution, it is to be mentioned that the authorisation to levy *ad hoc* rates is confined only to cases where such rates are individual – user – specific. It can not be for common user facilities or for revision of existing tariffs.
- (viii). It is possible that with the introduction of *ad hoc* rates there can be some laxity on the part of the major ports / private terminals to furnish requisite details to this Authority for setting final tariffs. In such cases, this Authority will be constrained to withdraw the general authorisation given to levy *ad hoc* rates and to order refund of the levies made, if the details required by the Authority are not furnished within the time limit stipulated.
- (ix). It has been the stated policy of this Authority to adopt uniform principles, approaches, and norms in the matter of tariff fixation at the Major Ports. It is, therefore, appropriate to prescribe the arrangement being ordered in the context of the proposal of the JNPT to the other major port trusts also and to the private terminals therein.

4. In the result, and subject to the observations made in paragraph 3 above, this Authority approves the following arrangement commonly for all the major port trusts and the private terminals therein:

- (i). Wherever a specific tariff for a service / cargo is not available in the notified Scale of Rates, the major port trusts / private terminals can submit a suitable proposal to this Authority.
- (ii). Simultaneously with the submission of proposal, the proposed rate can be levied on an *ad hoc* basis till the rate is finally notified by this Authority.
- (iii). The *ad hoc* rate to be operated in the interim period must be derived based on existing notified tariffs for comparable services / cargo; and, it must be mutually agreed upon by the Port / Terminal and the concerned user.
- (iv). The final rates fixed by this Authority will ordinarily be effective only prospectively. The interim rate adopted in an *ad hoc* manner will be recognised as such unless it is found to be excessive requiring some moderation retrospectively.

S. SATHYAM, Chairman

[ADVT III/IV/143/Ext.]